संपादकीय

मतदाता सूची विवाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना?

संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को देशभर में चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ, उसने भारतीय राजनीति में एक नए तूफान को जन्म दिया है। अब तक विपक्षी दल और विभिन्न सामाजिक संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। अब इस आंदोलन में एक नई और बड़ी मांग जुड़ गई है। यह मांग है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तत्काल रद्द करने और पुरानी मतदाता सूची को बहाल करने की है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने संविधान दिवस पर संविधान बचाओ और वोट चोरी के आरोपों के साथ देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किए। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में सफल विरोध कार्यक्रम हुए। आंदोलन में सामाजिक संगठनों, युवाओं और नागरिक अधिकार समूहों की भागीदारी बड़ी संख्या में देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया से बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदान सूची से अलग कर दिए गए हैं, जिसके कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। 13 करोड़ से अधिक नाम हटने का विवाद अब चरम स्तर पर पहुंच गया है। एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर है। सितंबर 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से लगभग 13.37 करोड़ नाम कम हुए हैं। यह संख्या पहले से दर्ज मतदाताओं का करीब 14.1 प्रतिशत है। हालांकि, यह कहना मुश्किल है, प्रारूप सूची से हटाए गए सभी नाम स्थायी रूप से काटे गए हैं। सभी वास्तविक मतदाता थे? ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। फिर भी बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो मतदाता हटाए गए थे उनकी संख्या बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण चुनाव आयोग निशाने पर है। इतने बड़े पैमाने पर नामों का कम होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

विपक्ष की मांग है, 2024 अथवा 2025 की पूर्ववर्ती मतदाता सूची को आधार बनाकर नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं, उन्हें बिना जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया के मतदाता सूची में वापस शामिल किया जाए। यह काम बीएलओ और रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में हो। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर रिपोर्ट सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत पड़ताल में दावा किया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम कर रहे दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में 14 बार निर्णयों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। यह मामला आयोग के आंतरिक निर्णयों और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा, एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 में कथित बदलाव और आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आयोग ने अपने जवाब में निर्णयों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब विपक्ष आयोग से आंतरिक फाइलों, निर्णयों और संबंधित रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। मतदान के आंकड़ों और ईवीएम से संबंधित विसंगतियों को लेकर भी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। प्रमाणों के साथ गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। अलग-अलग फॉर्म में दर्ज मतदाताओं और मतदान के आंकड़ों का अंतर चुनावी धांधली से जोड़ा गया है। इन मामलों में बृहबार दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही निष्कर्ष निकला गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। एसआईआर के मामले की सुनवाई लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 17 नवंबर की सुनवाई में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित है।

भारतीय वैज्ञानिकों को संसाधन और सम्मान की जरूरत

भारतीय वैज्ञानिकों को बेहतर शोध के लिए उचित अवसर, स्वायत्तता और पेशेवर सम्मान की आवश्यकता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। जहाँ एक ओर देश में नई शोध योजनाएँ शुरू की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कार्य-संस्कृति और संसाधनों को लेकर चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।

हमारे विद्वानों की श्रृंखला में ताजा नाम बेंगलुरु के मैथमैटिशियन ऋद्धि प्रतिम बसु का जुड़ा है जिन्हें उनके द्वारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने, दशकों पुरानी स्लो-बॉन्ड प्रॉब्लम सुलझाने, रैंडम ग्राफ और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर उनके काम के लिए मैथमैटिकल साइंसेज में इंफोसिस प्राइज-2026 मिला है। इस पहेली को सुलझा कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक प्वाइंट पर थोड़ी सी भी रुकावट पूरे सिस्टम में फ्लो को धीमा कर सकती है।

एक अध्ययन के अनुसार कोलकाता के रहने वाले ऋद्धि प्रतिम बसु ने स्टैनफोर्ड से जुड़ने से पहले यू.सी. बर्कले से अपनी पीएच. डी. पूरी की। उनकी इस उपलब्धि ने भारत के महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बसु (बोस) (1894-1974) की याद ताजा कर दी है जिनकी प्रतिभा का दुनिया ने लोहा तो माना।

आपको बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स और सांख्यिकी के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। वर्ष 1924 में कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय सत्येंद्र नाथ बोस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध-पत्र लिखा। इसमें उन्होंने क्लासिकल भौतिकी की मदद लिए बिना, प्लांक के क्वांटम रेडिएशन नियम को व्युत्पन्न किया।

उन्होंने अपना शोध-पत्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा, जिन्होंने इसके महत्व को पहचाना, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया और इसे प्रकाशित करवाने में सत्येंद्र नाथ बोस की सहायता की। इन दोनों के संयुक्त कार्य ने बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव रखी और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के अस्तित्व की भविष्यवाणी की।

भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में बोसोन नाम रखा था, ये सब-एटॉमिक कणों का एक वर्ग है जिनका स्पिन पूर्णांक होता है इनमें फोटोन और हिग्स बोसोन शामिल हैं।

बर्न में अल्बर्ट आइंस्टीन के घर में सत्येंद्र (बोस) की तस्वीरें, उनके शोध-पत्र आदि मौजूद हैं।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि सत्येंद्र नाथ बोस के काम पर आधारित शोध के लिए दूसरे लोगों को विज्ञान के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार दिए गए, लेकिन स्वयं सत्येंद्र नाथ बोस को इसके लिए 4 बार मनोनीत किए जाने के बावजूद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया।

उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी खोज को मान्यता मिली तो नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने यह कह कर देने से इन्कार कर दिया कि वे मृतक को पुरस्कार देते ही नहीं।

लेकिन क्या हम अपने वैज्ञानिकों का उतना सम्मान करते हैं, जितना हमें करना चाहिए? क्या कहीं भी हमारे वैज्ञानिकों की कोई प्रतिमा है? क्या भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए एक दिन भी समर्पित नहीं कर सकते ? हम जो आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों की बात करते हैं, भारत की सर्वप्रथम विश्व को शून्य देने की बात करते हैं, हमें अपने महान वैज्ञानिकों का सम्मान भी करना चाहिए। शायद समर्थन की कमी के कारण ही, भारतीय वैज्ञानिकों में से केवल डॉ. सी.वी. रमन को ही 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला।

ऐसा नहीं है कि भारत में महान प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की कमी है, हमारे वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र-भौतिकी, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण आविष्कार और खोजें की हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सुब्रह्मण्यन, चंद्रशेखर, सर एम. विश्वेश्वरैया, यल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव आदि। ऐसी भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भी लंबी कतार है, जैसे अन्ना मणि, असीमा चटर्जी, कमला सोहोनी, राजेश्वरी चटर्जी, इंदिरा हिंदुजा, अनेकों और भी।

हमारे वैज्ञानिक नासा में जाते हैं और दुनिया भर के देशों में काम करते हैं। नासा के नाम से हमारे मन में कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स का नाम आता है, पर क्या हम जानते हैं कि कमलेश लुल्ला नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में पृथ्वी अवलोकन के मुख्य वैज्ञानिक हैं? शर्मीला भट्टाचार्य वर्तमान में नासा एम्स रिसर्च सेंटर में एस्ट्रोबायोनिक्स की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं। अश्विन वासवड़ा कैलिफोर्निया में नासा की जैट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में एम.एस.एल. क्यूरियोसिटी रोवर के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

तो हम अपने ही देश में उन्हें उनका बनता सम्मान क्यों नहीं देते ? हम जो शुरू से ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में स्वयं को विश्व में अग्रणी मानते आ रहे हैं, क्या अब हमारा विज्ञान की ओर रुझान कम हो गया है ?

यदि हम अपने विद्वानों को प्रोत्साहित करते या अपने प्राचीन विद्वानों के योगदान को याद रखते तो न जाने और कितनों को यह पुरस्कार मिल सकता था। निश्चय ही यह एक महान उपलब्धि है, परंतु आज यह बात कितने भारतीयों को मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक कितने प्रतिभाशाली थे और हैं।

ध्यान रहे कि कई शोध संस्थानों में वैज्ञानिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बजाय प्रशासनिक नियंत्रण और पद के आधार पर सम्मान मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

बेहतर अवसरों, कार्य-वातावरण और सम्मान की कमी के चलते कई शोधकर्ता विदेश जाते हैं या देश के संस्थानों से इस्तीफा देते हैं।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिकों को लंबे समय तक जटिल विषयों पर काम करने, असफलता से सीखने की छूट और केवल कागजी मानकों से परे हटकर गुणवत्तापूर्ण काम के आधार पर आंका जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन , अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना, रामानुजन फेलोशिप और इनसपायर जैसी पहलों के माध्यम से शोध को बढ़ावा और वित्तपोषण दिया जा रहा है।

होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम साराभाई और जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों के योगदान ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को मजबूत पहचान दिलाई है। इनके योगदान को प्रेरणा समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

मंगल की ओर बढ़ते मानव कदम

वैसे तो रात होते ही आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन इसानों के लिए पृथ्वी के बगल में सदा से ही आकर्षण का केन्द्र रहा एक खूबसूरत लाल ग्रह मौजूद है, जिसे 'रेड प्लेनेट' अथवा 'मंगल' के नाम से जाना जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है, जो रात के समय लाल रंग का दिखाई देता है। इसी लाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रतिवर्ष 28 नवम्बर को 'लाल ग्रह दिवस' (रेड प्लेनेट डे) मनाया जाता है। यह दिवस 28 नवम्बर 1964 को नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा अंतरिक्ष यान 'मेरिनर-4' के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है, जो कई असफल मिशनों के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। करीब आठ महीने की यात्रा करने के बाद यह अंतरिक्ष यान 14 जुलाई 1965 को लाल ग्रह पर पहुंचा था। 28 नवम्बर 1964 को नासा ने जब पहली बार 'मेरिनर-4 रोबोटिक इंटरप्लेनेटरी प्रो' लांच किया था, तब अनौपचारिक छुट्टी की घोषणा की गई थी और सभी ने नासा की इस सफलता को उत्साहपूर्वक मनाया था। मेरिनर-4 को फ्लाई-बाय के दौरान डेटा एकत्र करने, ग्रहों की खोज और मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अवलोकन को सक्षम करने तथा उस डेटा को पृथ्वी पर लोगों को वापस रिले करने के लिए बनाया गया था। अपने 228 दिनों के सफर को सफलतापूर्वक तय करने के बाद मेरिनर-4 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना था, जिसे नासा द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। उसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत की थी।

अब तक 14 मंगल मिशन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं, जहां मानव निर्मित वस्तुएं इस ग्रह पर उतरी। भारत भी इसरो के जरिये मंगल ऑर्बिट तक पहुंचने के अपने 'मंगल मिशन' में सफल हो चुका है। मंगल को जानने के लिए अब तक दुनियाभर में शुरू किए गए दो तिहाई अभियान असफल रहे हैं लेकिन भारत 24 सितम्बर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही विश्व में अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। सूर्य से चौथा ग्रह 'लाल ग्रह' यानी मंगल है और मंगल तथा पृथ्वी का गहरा संबंध माना जाता रहा है। मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और अपने साथी स्थलीय ग्रहों की ही तरह इसमें भी एक केन्द्रीय कोर, एक चट्टानी आवरण और एक ठोस परत है। धूल भरी, ठंडी, रेगिस्तानी दुनिया में इसका वातावरण बहुत पतला है। मौसमों, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, घाटियों, विलुप्त ज्वालामुखी और इस बात के प्रमाण होने के साथ-साथ कि यह एक समय और भी अधिक सक्रिय था, मंगल एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी के कारण, मंगल ग्रह पर ऐसे मौसम का अनुभव होता है, जो अत्यधिक तापमान से बना होता है और तापमान -191 डिग्री फोरेनहाइट से 81 डिग्री तक जा सकता है। लाल ग्रह के बारे में जानने के लिए कई एस्ट्रोनॉमी क्लब की भी शुरुआत की गई है, जो मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियों को एक-दूसरे से बांटने का काम करते हैं।

मंगल ग्रह के चारों ओर कोई वलय नहीं हैं। कई अध्ययनों से पता चल चुका है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की स्थलाकृति से काफी मिलता-जुलता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह अलग-अलग मौसम हैं लेकिन वे पृथ्वी पर मौसम की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं। चूंकि मंगल ग्रह के बहुत से गुण पृथ्वी की तरह ही हैं, इसीलिए पृथ्वी के पर्यावरण की तरह मंगल के पर्यावरण को समझकर यह माना जाता है कि बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हुआ होगा और यह भी माना जाता है कि भविष्य में भी मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण मंगल की कक्षा पूरी होने की गति बहुत धीमी है और इसी कारण मंगल ग्रह पर एक वर्ष में करीब 687 दिन बीतेंगे, जो पृथ्वी पर एक वर्ष से लगभग दोगुना समय है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में मंगल ग्रह को 1.88 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी का करीब एक-तिहाई है और गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न खिंचाव के परिणामस्वरूप ही पृथ्वी पर पहले व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 100 पाउंड है तो अंतरिक्ष में उसका वजन केवल 38 पाउंड ही होगा। यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? दरअसल यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढ़की हुई होती है। मंगल ग्रह की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों के कारण ही यह ग्रह लाल रंग का है। नासा के मुताबिक मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा में मौजूदगी है और वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार ऑक्सीजन तथा नमी के सम्पर्क में आने पर पृथ्वी पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार मंगल की मिट्टी में मौजूद लौह खनिज में जंग लग गया है और उसी कारण यह लाल नजर आती है। मंगल की सतह पर काफी मात्रा में लोहा है और जब यह ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। पृथ्वी अपने वायुमंडल के कारण नीले रंग की दिखाई देती है लेकिन मंगल का जंग जैसा लाल रंग इसकी मिट्टी में ऑक्सीकृत लोहे के कारण आता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर बहुत सारी चट्टानें लोहे से भरी हुई हैं और जब वे बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आती हैं तो ऑक्सीकरण करती हैं और लाल हो जाती हैं। जब उन चट्टानों से जंग लगी धूल वायुमंडल में फैलती है तो इससे मंगल ग्रह का आकाश लाल या गुलाबी दिखने लगता है।

भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास का रजत सम्मान

आईआईटीएफ-2026 में रजत पुरस्कार से सम्मानित हुआ रेलवे मंडप भाप इंजन से वंदे भारत स्लीपर तक 173 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का नया अध्याय; 99.6 प्रतिशत ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण,स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक रेल तकनीक बनी दर्शकों का बना आकर्षण केंद्र

भारतीय रेलवे की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत,आधुनिक तकनीकी क्षमता और विकास की निरंतर यात्रा को 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ-2026) में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में रेल मंत्रालय के मंडप को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'विकास और विरासत' की व्यापक अवधारणा पर आधारित इस आयोजन में भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी ने आगंतुकों के साथ निर्णायक मंडल का भी विशेष ध्यान आकर्षित किया।यह सम्मान केवल एक आकर्षक प्रदर्शनी की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस भारतीय रेल व्यवस्था की विकास यात्रा की गाथा का प्रतीक है,जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में डेढ़ शताब्दी से अधिक समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रेलवे का इतिहास केवल रेलगाड़ियों और पटरियों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यापारिक विस्तार और राष्ट्रीय एकीकरण की एक जीवंत गाथा है। सर्व विदित रहे कि भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी ने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी। उस ऐतिहासिक रेलगाड़ी में 14 डिब्बे और लगभग 400 यात्री सवार थे। भाप इंजन से शुरू हुई यह यात्रा धीरे-धीरे देश के दूरदराज के शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंची। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में विभिन्न रियासतों और निजी व्यवस्थाओं से जुड़ी 42 रेल प्रणालियों को एकीकृत कर भारतीय रेलवे के व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आज यही रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। समय के साथ भारतीय रेलवे ने तकनीकी बदलावों को अपनाते हुए विकास की लंबी मंजिल तय की है। वर्ष 1925 में मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेल सेवा शुरू होना भारतीय रेल इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव था। भाप इंजनों के दौर से डीजल और फिर विद्युत इंजनों तक पहुंचने वाली इस यात्रा ने रेल परिचालन की गति, क्षमता और दक्षता को नई दिशा दी। आज भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। यह उपलब्धि ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक रेल परिचालन के क्षेत्र में भारत की बड़ी प्रगति को दर्शाती है। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 25 हजार रेलगाड़ियों का संचालन करते हुए देश के करोड़ों लोगों की जीवनरेखा बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने लगभग 741 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया और माल ढुलाई में 1,670 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। यह उपलब्धियाँ बताती हैं कि भारतीय रेलवे केवल यात्री परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि कृषि, उद्योग, व्यापार, खनन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का भी प्रमुख आधार है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक उपलब्धियों को आईआईटीएफ-2026 के रेलवे मंडप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल रहा। लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्राओं को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विकसित इस आधुनिक ट्रेन में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समकालीन तकनीक का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे के विभिन्न रेल नेटवर्क पर संचालित होने वाली अनेक श्रेणियों की ट्रेनों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। इन मॉडलों के माध्यम से आगंतुकों को भारतीय रेल के बदलते स्वरूप, इंजीनियरिंग क्षमता और भविष्य की परिवहन योजनाओं को समझने का अवसर मिला। रेलवे की आधुनिक उपलब्धियों में स्वदेशी 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी विशेष महत्व रखती है। यह तकनीक रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने और संभावित टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास, समर्पित मालवहन गलियारों और डिजिटल यात्री सेवाओं ने रेलवे के आधुनिकीकरण को नई गति दी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप देश में आधुनिक रेल इंजन और डिब्बों का निर्माण भी भारतीय रेलवे की औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर रहा है। भारतीय रेलवे की यह विकास यात्रा विरासत और नवाचार के सुंदर समन्वय का उदाहरण है। एक ओर देश के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, पुराने पुल, भाप इंजनों की स्मृतियाँ और रेल संस्कृति हमारी विरासत का हिस्सा हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक विद्युत इंजन, स्वदेशी सुरक्षा तकनीक, तेज गति वाली ट्रेनें और डिजिटल सुविधाएं भविष्य के भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।आईआईटीएफ-2026 में मिला सिल्वर पुरस्कार इसी बदलते भारतीय रेलवे की उपलब्धियों का सम्मान है। यह सम्मान उस संस्थागत संकल्प को भी रेखांकित करता है, जिसके माध्यम से भारतीय रेलवे सुरक्षित, तेज, स्वच्छ, आधुनिक और विश्वस्तरीय रेल संपर्क व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भाप इंजन की ऐतिहासिक सीटी से लेकर वंदे भारत स्लीपर की आधुनिक तकनीक तक भारतीय रेल की यह यात्रा सचमुच विकसित भारत के सपने को पटरियों पर गति देने वाली गौरव की गाथा है। जिसकी गुंज भारत के सीमाओ से बाहर निकल कर आज विदेशों में भी चर्चा व चिन्तन का केन्द्र बनने लगा है।

शीतकालीन सत्र : परिसीमन -महिला आरक्षण विधेयक से सरकार की अग्निपरीक्षा

संसद का आगामी सत्र देश की राजनीति के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रियों को 15 दिसंबर से पहले संसद सत्र की तैयारियां पूरी करने और सत्र से पहले विदेश यात्राओं से बचने की सलाह देना इस बात का संकेत है कि सरकार आगामी संसदीय कार्यवाही को लेकर बेहद गंभीर है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब संसद के मानसून सत्र के स्थगित होने के 100 से अधिक दिन बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। विपक्ष जहां संसद सत्र बुलाने में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के सामने परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां खड़ी हैं।

दरअसल, संसद का सत्र केवल विधायी कार्यवाही का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद, जवाबदेही तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच भी है। ऐसे में संसद की बैठक बुलाने और उसे समय पर संचालित करने को लेकर उठने वाले सवालों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। संसद की कार्यवाही में निरंतरता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।

मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था। इसके बाद से सत्रावसान नहीं होने और अगले सत्र की तारीख को लेकर अनिश्चितता ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसद की बैठक बुलाने में देरी कर रही है। हालांकि, सरकार के पास संसदीय कार्यक्रम निर्धारित करने का संवैधानिक और प्रक्रियागत अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद को राजनीतिक सुविधा के अनुसार चलाने की धारणा मजबूत होने दी जाए। संसद का महत्व किसी एक दल या सरकार से बड़ा है।

आगामी सत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक माना जा रहा है। सरकार यदि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करती है तो यह उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक और विधायी परीक्षा होगी। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा की 543 सदस्यीय वर्तमान संरचना में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 362 सदस्यों का है, जबकि राजनीतिक चर्चाओं में 361 मतों का आंकड़ा भी सामने रखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को अपने मौजूदा संख्याबल से आगे बढ़कर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास वर्तमान में लगभग 320 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। इस स्थिति में सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा। केवल गठबंधन के संख्याबल के भरोसे संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संभव नहीं दिखता। यही कारण है कि सरकार को क्षेत्रीय दलों और विपक्ष के कुछ घटकों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ सकता है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महिला आरक्षण जैसे व्यापक सामाजिक महत्व के विषय को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाकर देखा जाएगा? महिलाओं को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है। लेकिन यदि इस व्यवस्था को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर लागू किया जाता है तो इसके राजनीतिक, सामाजिक और संघीय प्रभावों पर गंभीर चर्चा आवश्यक हो जाती है।

परिसीमन का मुद्दा केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के संघीय ढांचे, राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन से है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों का संसद में सापेक्षिक राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।

यह चिंता पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघीय देश में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है।सरकार द्वारा लोकसभा की कुल सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के संभावित फॉर्मूले पर विचार इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने और 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हिस्सेदारी को संरक्षित रखने की संभावना पर चर्चा हो रही है। यदि ऐसा कोई फार्मूला सामने आता है तो वह दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।लेकिन इस विषय पर केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि प्रस्तावित परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन किस प्रकार बना रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और विकास के प्रयासों की सफलता के कारण राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े।

आगामी सत्र में विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी सरकार को घेर सकता है। विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची में संभावित ग